

फूड सिक्युरिटी : दिल्ली वालों को सस्ती चीनी देने की तैयारी

कुछ मीठा हो जाए



■ वीरेंद्र वर्मा, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार का फूड एंड सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट अब फूड सिक्युरिटी स्कीम में चीनी की मिठास भी धोलने की तैयारी कर रहा है। एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसके तहत राजधानी के 73 लाख लोगों को गेहूं और चावल के साथ कंट्रोल रेट पर चीनी भी मिलेगी। हर व्यक्ति को हर महीने में 400 ग्राम चीनी मुहैया कराई जाएगी। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं तो उन्हें 2 किलो चीनी मिलेगी। यह चीनी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। मार्केट में चीनी का रेट फिलहाल 35 रुपये किलो के आसपास चल रहा है। फूड एंड सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट ने यह प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्टडी के लिए भेजा है।

माना जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से हरी झंडी मिलने के बाद इसे 16 मई के बाद लागू किया जा सकता है। राजधानी में अभी तक बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारियों को चीनी मिलती थी। लेकिन नई स्कीम के तहत आने वाले सभी 73 लाख लोगों को दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है।

राजधानी में साल 2001 से पहले

कितने कार्ड

कार्ड	संख्या	फैमिली
बीपीएल	12, 57,000	3.25 लाख
अंत्योदय	5,03,000	1.03 लाख
फूड सिक्युरिटी	73,00,000	34 लाख



जुलाई के अंत तक बंद होंगे बीपीएल कार्ड, फूड सिक्युरिटी और अंत्योदय कार्ड चलेंगे

73 लाख को हर महीने 400 ग्राम चीनी देने का प्रपोजल

13 रुपये 50 पैसे का रेट, फूड एंड सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट का प्रस्ताव

हर व्यक्ति को राशन कार्ड के जरिए सस्ती चीनी मुहैया कराई जाती थी, लेकिन 2001 के बाद इसे बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक फूड एंड सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट फूड सिक्युरिटी स्कीम को जुलाई के अंत तक पूरी तरह से लागू कर देगा। उसके बाद बीपीएल कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। जुलाई के अंत या अगस्त के शुरु में सिर्फ फूड सिक्युरिटी स्कीम के तहत वाले कार्ड और अंत्योदय वाले कार्ड ही चलेंगे।

राजधानी में अभी बीपीएल कार्डधारी 3 लाख, 25 हजार फैमिली आती हैं यानी बीपीएल कार्ड के तहत 12 लाख 57 हजार लोग आते हैं। अंत्योदय कार्ड वाली फैमिली 1 लाख 3 हजार आती हैं यानी इस

स्कीम के तहत 5 लाख 3 हजार लोग आते हैं। अभी इन दोनों कैटेगरी के कार्ड धारियों को प्रति व्यक्ति 1 किलो 200 ग्राम चीनी मिलती है। यानी इनको चीनी मुहैया कराने के लिए 2160 मिट्रिक टन चीनी की हर महीने जरूरत पड़ती है। अगर दिल्ली सरकार 73 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 400 ग्राम चीनी मुहैया कराती है तो दिल्ली सरकार को 2612 मिट्रिक टन चीनी की जरूरत पड़ेगी।

पहले केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को चीनी मुहैया कराई जाती है, लेकिन अब केंद्र सरकार प्रति किलो 18 रुपये 50 पैसे की दर से सब्सिडी देती है।

दिल्ली सरकार को चीनी 33 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी पड़ती है। इसलिए दिल्ली सरकार प्रति किलो चीनी पर 1 रुपये 50 अपनी ओर से देती है और उपभोक्ताओं को चीनी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मुहैया कराई जाती है। अगर सभी 73 लाख लोगों को इस दर पर चीनी मुहैया करानी है तो सरकार पर हर महीने 1 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और सालाना 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।

Navbharat Times

1-May-2014

✓